RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 310
दि. 14.03.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से 'पीएम-किसान योजना' की 22वीं किस्त जारी की

- 22वीं किस्त के तहत गुजरात के 49.59 लाख धरती पुत्रों को 1028 करोड़ रुपए सहित देश के 9.32 करोड़ किसानों को 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली
- गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' समारोह आयोजित हुआ
- कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी और राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा की प्रेरक उपस्थिति
- कार्यक्रम में महानुभावों ने किसानों को विभिन्न कृषि-उन्मुख योजनाओं की सहायता वितरित की
- राज्य के किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा

जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना' की 22वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश के 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए हस्तांतरित की गई। इसके अंतर्गत गुजरात के 49.59 लाख किसानों को भी पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत 1,028 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि मिली है।

गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय 'पीएम किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी और राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा मौजूद रहे।

समारोह में मुख्यमंत्री के करकमलों से लाभार्थी किसानों को कृषि और बागवानी की विभिन्न खेती-उन्मुख योजनाओं की सहायता का वितरण किया गया। इसके बाद, महानुभावों सहित राज्य के हजारों किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किसान हितैषी शासन का मंत्र दोहराते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उन्होंने किसानो की समस्याओं को संवेदना के साथ सुना और समझा है। अतीत में हमने पानी की जिन विकट परिस्थितियों को देखा है, उनसे किसानों को बाहर लाने का भगीरथ काम प्रधानमंत्री ने किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा कैनाल के नेटवर्क के जरिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर खेती को नया जीवन दिया है। पानी के सुनियोजित आयोजन से किसानों को होने वाली परेशानियां खत्म हो गई हैं। बिजली की समस्या की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले किसानों को रात में बिजली मिलने के कारण काफी दिक्कत होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज गुजरात में 24 घंटे और 365 दिन बिजली उपलब्ध है। लगभग 96 से 98 फीसदी किसानों को अब दिन के दौरान बिजली की आपूर्ति की जाती है।

उन्होंने कहा कि सरकार बरसाती पानी का संग्रहण करने और भूगर्भ जल का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हर विधायक को 50 लाख रुपए का विशेष अनुदान आवंटित किया है, जिसका उपयोग केवल जल संचय और पानी को जमीन में उतारने के कार्यों के लिए करना होगा। इससे भविष्य में किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कम उम्र में दिखाई दे रहे कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे रोगों के पीछे रासायनिक खेती एक बड़ा कारण हो सकता है। उन्होंने राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत का जिक्र करते हुए कहा कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को इस बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। भूमि की उर्वरता और कार्बन की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक कृषि ही एकमात्र विकल्प है।

मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को और तेजी देने को कहा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने खेतों की मेड़ों पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर 'ग्रीन कवर' को बढ़ाने में योगदान दें, ताकि वातावरण में आने वाले अनियमित बदलावों से बचा जा सके।

वर्तमान वैश्विक हालात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि गैस सिलेंडर या दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी की अफवाहों से भ्रमित न हों। हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मजबूत नेतृत्व में 'विकसित गुजरात' के जरिए 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में किसान उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था का दिल हैं और उनका कल्याण ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दिन-रात मेहनत कर पूरे परिवार का भरण-पोषण करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए आज 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना के अंतर्गत 22वीं किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या अन्य कोई मुसीबत, सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.सी. मीणा ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में गांधीनगर महानगर पालिका की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, अग्रणी श्री आशीषभाई दवे, सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सोलंकी, मत्स्योद्योग आयुक्त श्री विजय खराड़ी, जिला कलेक्टर श्री जे.एन. वाघेला सहित कई उच्च अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

महानगर में 'गैस स्कैम' का जाल, कनेक्शन कटने का डर दिखाकर साइबर ठगों की बड़ी ठगी

जीएनएस)। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों एक खतरनाक साइबर ठगी का जाल तेजी से फैल रहा है, जिसे लोग 'गैस स्कैम' के नाम से पहचानने लगे हैं। गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और देखते ही देखते उनके बैंक खातों से लाखों रुपये साफ किए जा रहे हैं। पिछले चार दिनों में ही इस तरह की घटनाओं ने कई परिवारों को आर्थिक रूप से झटका दिया है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने केवल चार दिनों के भीतर लगभग 26 लाख 43 हजार रुपये की ठगी कर ली है, जबकि पिछले दस दिनों में अलग-अलग पुलिस थानों में इस तरह के कम से कम दस मामले दर्ज किए गए हैं।

यह पूरा फर्जीवाड़ा महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) के नाम पर किया जा रहा है। ठग खुद को इस गैस कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते हैं और दावा करते हैं कि उनके घर का गैस बिल बकाया है। इसके बाद वे कहते हैं कि यदि तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो उसी दिन शाम तक गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। अचानक आई इस चेतावनी से कई लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे-समझे ठगों के बताए निर्देशों का पालन करने लगते हैं। इसी घबराहट का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच बना लेते हैं।

पुलिस के अनुसार ठग सबसे पहले फोन कॉल या मैसेज के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं। वे बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बातचीत करते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि वे सचमुच गैस कंपनी के कर्मचारी हैं। बातचीत के दौरान वे कहते हैं कि बिल की "वेरिफिकेशन प्रक्रिया" पूरी करनी होगी। इसके लिए वे एक एपीके फाइल भेजते हैं और बताते हैं कि केवल 13 या 21 रुपये का भुगतान करना होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड करता है, उसके मोबाइल फोन का नियंत्रण धीरे-धीरे ठगों के हाथ में चला जाता है।

इन दिनों व्हाट्सएप पर 'mahanagar gas.apk' नाम से फाइल भेजे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इस फाइल के साथ संदेश लिखा होता है कि यदि शाम तक बिल जमा नहीं किया गया तो गैस लाइन काट दी जाएगी। कई लोग डर के कारण दिए गए नंबर पर फोन करते हैं। इसके बाद ठग उन्हें एक लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि उस पर क्लिक करके भुगतान कर दें। जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है या एपीके फाइल इंस्टॉल करता है, मोबाइल में मौजूद कई संवेदनशील जानकारियां ठगों तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद कुछ ही मिनटों में बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं।

इस साइबर ठगी का सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग नागरिकों पर पड़ रहा है। कई मामलों में बुजुर्गों को फोन कर डराया गया कि उनका गैस कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। घबराकर उन्होंने ठगों द्वारा भेजी गई फाइल डाउनलोड कर ली या लिंक पर क्लिक कर दिया और कुछ ही देर में उनके बैंक खातों से लाखों रुपये गायब हो गए।

उदाहरण के तौर पर परेल इलाके के 70 वर्षीय रमेश सुराणा को ठगों ने अपना शिकार बनाया। उनसे लगभग 6.90 लाख रुपये की ठगी की गई। इसी तरह वडाला के 72 वर्षीय विजय चौहान से 8.25 लाख रुपये निकाल लिए गए। वहीं विले पार्ले के दो बुजुर्ग नागरिकों शामल सप्रे और शांतनु कर्णिक से क्रमशः 4.36 लाख और 6.99 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। इन सभी मामलों में ठगी का तरीका लगभग एक जैसा था—फोन कॉल, एपीके फाइल और भुगतान का झांसा।

केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा भी इस साइबर जाल में फंस रहे हैं। कांजुरमार्ग के 33 वर्षीय समर चव्हाण से 2.82 लाख रुपये की ठगी की गई, जबकि बोरिवली के 37 वर्षीय सतीश अमरगोंड से 4.18 लाख रुपये निकाल लिए गए। पुलिस का कहना है कि ठग बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोगों को फंसाते हैं और कई बार स्थानीय भाषा का उपयोग करके भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं।

हाल ही में एक और मामला सामने आया जिसमें डोंबिवली की एक महिला से लगभग तीन लाख रुपये की ठगी की गई। ठगों ने स्मिता राणे नामक महिला के पति को एक फर्जी एसएमएस भेजा। उस संदेश में लिखा था कि फरवरी महीने का गैस बिल सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है और यदि तुरंत प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद खुद को गैस कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने उन्हें एक संदिग्ध लिंक भेजा। महिला ने उस लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंकिंग जानकारी भर दी, जिसके बाद उनके खातों से कुल 2,99,500 रुपये निकाल लिए गए। इसमें 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड से और 99,500 रुपये डेबिट कार्ड से निकाले गए।

जांच एजेंसियों के अनुसार यह साइबर ठगी केवल मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। हाल ही में पटना में पुलिस ने छापेमारी कर चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था, जो महानगर गैस कनेक्शन के नाम पर एपीके फाइल भेजकर लोगों को ठग रहे थे। पुलिस को इस मामले की शिकायत एनसीआर के माध्यम से मिली थी, जिसके बाद पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में कार्रवाई की गई।

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी नीतिश चंद्र धारिया ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उनके अनुसार यह गिरोह अब तक 20 से अधिक राज्यों में सक्रिय रहा है और हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अपराधियों ने यह भी बताया कि उन्हें इस काम के लिए ठगी की रकम का लगभग 40 से 45 प्रतिशत कमीशन मिलता था। ठगों का तरीका इतना सुनियोजित था कि वे लोगों से बातचीत करते समय स्थानीय मराठी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिससे लोगों को शक न हो।

राज्यसभा चुनाव से पहले 'रेसॉर्ट पॉलिटिक्स' तेज ओडिशा के कांग्रेस विधायक कर्नाटक पहुंचे

जीएनएस)। देश की राजनीति में राज्यसभा चुनावों से पहले एक बार फिर 'रेसॉर्ट पॉलिटिक्स' चर्चा में आ गई है। ओडिशा में होने वाले राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राज्य से बाहर भेज दिया है। इसी क्रम में ओडिशा के कांग्रेस विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक रिसॉर्ट में ठहराया गया है। खरीद-फरोख्त और क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच उठाए गए इस कदम ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जानकारी के अनुसार इन विधायकों ने शुक्रवार को डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की। यह बैठक बेंगलुरु के

पास स्थित वंडरला रिसॉर्ट में हुई, जहां फिलहाल ओडिशा के कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। इस मुलाकात में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भक्त चरण दास भी मौजूद थे।

मुलाकात के बाद डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि बेंगलुरु में ओडिशा के कांग्रेस विधायकों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि विधायकों की एकता और दृढ़ संकल्प यह दर्शाता है कि कांग्रेस नेताओं का लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प मजबूत है और इसे किसी भी तरह के दबाव या प्रयास से कमजोर नहीं किया जा सकता।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह कदम पूरी तरह एहतियाती है। दरअसल, राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच खरीद-फरोख्त या क्रॉस वोटिंग की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसी संभावना को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया है, ताकि मतदान तक पार्टी की एकता बनी रहे।

सूत्रों का कहना है कि ओडिशा में राज्यसभा की एक सीट के लिए राजनीतिक समीकरण अचानक बदल गए, जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। इसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई और कांग्रेस को आशंका हुई कि उसके कुछ विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है।

लापता लोगों के मामलों पर सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग, पांच राज्यों से मांगी जवाबदेही

जीएनएस)। देश में लगातार बढ़ते लापता लोगों के मामलों को लेकर अब मानवाधिकार संस्थाएं भी गंभीर हो गई हैं। इस मुद्दे को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इसे गंभीर मानवाधिकार समस्या बताया है। आयोग ने इस मामले में पांच राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा है और संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

आयोग ने जिन राज्यों को नोटिस भेजा है उनमें ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में लापता लोगों की संख्या और उन्हें तलाशने की प्रक्रिया को लेकर आयोग ने चिंता व्यक्त की है। आयोग का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का लंबे समय तक पता नहीं चल पाता, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला भी बन जाता है।

आयोग ने इन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि राज्य सरकारों ने लापता लोगों की खोज के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं और आगे इस समस्या को रोकने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। आयोग यह भी जानना चाहता है कि पुलिस और प्रशासनिक तंत्र इस दिशा में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और मामलों के समाधान की वर्तमान स्थिति क्या है।

इसके साथ ही आयोग ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से भी इन राज्यों में लापता लोगों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी है। एनसीआरबी देश भर में अपराध से संबंधित आंकड़े एकत्र करता है और विभिन्न प्रकार के अपराधों के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। आयोग इन आंकड़ों के आधार पर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि लापता लोगों की समस्या किस हद तक गंभीर है और किन क्षेत्रों में स्थिति अधिक चिंताजनक है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बिहार में यह समस्या काफी लंबे समय से सामने आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 से हर साल लगभग 12 से 14 हजार लोगों के लापता होने के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की बताई जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में से केवल लगभग दो-तिहाई बच्चों को ही खोजा जा सका है, जबकि शेष बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के लापता होने के मामलों के पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं। कई बार बच्चे घर से भाग जाते हैं, जबकि कई मामलों में उन्हें बहला-फुसलाकर ले जाया जाता है। कुछ मामलों में संगठित अपराध गिरोह भी बच्चों को निशाना बनाते हैं और उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेल देते हैं।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के मामलों में भी इन राज्यों की स्थिति चिंताजनक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। नाबालिग लड़कों की तस्करी के मामलों में ओडिशा शीर्ष पर है, जबकि नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर बताया गया है।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि लापता बच्चों का एक बड़ा हिस्सा अक्सर संगठित अपराध गिरोहों के हाथों में पहुंच जाता है। कई बच्चों को भीख मंगवाने, बाल मजदूरी कराने या अन्य अवैध कार्यों में जबरन लगाया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें देह व्यापार जैसे गंभीर अपराधों में भी धकेल दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं बल्कि बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों का भी गंभीर हनन करती हैं।

इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। आयोग का कहना है कि यदि रिपोर्टों में बताए गए तथ्य सही पाए जाते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा और संबंधित राज्यों को अपनी व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

आयोग ने राज्यों से यह भी पूछा है कि लापता लोगों के मामलों की जांच को तेज करने, पीड़ितों को जल्द ढूंढने और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अब तक कौन-कौन से उपाय किए गए हैं।

संपादकीय

मृत्यु में गरिमा

किसी भी समाज में यह प्रबल धारणा रही है कि परिवार के किसी सदस्य की तब तक सेवा की जाए, जब तक उसके प्राण कुदरती तौर पर न निकल जाएं। खासकर भारतीय समाज में इस मुद्दे को लेकर गहरी संवेदनशीलता रही है। कई स्थानों पर तो अपने आत्मीय की मृत्यु के बाद भी उसे वर्षों तक जीवन लौटने की आस में घर पर रखा गया। लेकिन जब कोई अपना प्रिय उस स्थिति में पहुंच जाए, जहां से सामान्य जीवन में लौट पाना संभव ही न हो, तो बदलते वक्त के साथ कानून के दायरे में उसकी मुक्ति की भी बात होने लगी है। हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट का 13 वर्ष से कोमा में रहने वाले एक युवा के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय, जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर भारत में विकसित होते न्यायशास्त्र में नया मोड़ है। किसी असाध्य स्थिति में कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने वाला यह फैसला, अदालत द्वारा पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पहला व्यावहारिक प्रयोग है। निस्संदेह,यह मामला उन रोगियों के परिवारों के सामने उपस्थित पीड़ादायक दुविधा को ही उजागर करता है, जिनके ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती। जो महज चिकित्सकीय मदद से ही जीवित रहते हैं। इस मामले में चिकित्सा बोर्डों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निरंतर उपचार का कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं था। इससे केवल जैविक अस्तित्व को ही लंबा खींच दिया गया। बहरहाल, इस बाबत अदालत की स्वीकृति एक कठिन सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन की गरिमा, मृत्यु में भी गरिमा तक विस्तारित होनी चाहिए। निस्संदेह, भारत में इच्छामृत्यु पर कानूनी प्रगति धीमी रही है। इस मामले में पहली बार अरुणा शानबाग मामले में ध्यान दिया गया था। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार देने के साथ यह मुद्दा अपने चरम पर पहुंचा।

दरअसल, इच्छामृत्यु से जुड़ी दुविधा, इससे जुड़े सिद्धांतों के क्रियान्वयन की अनिश्चितता को लेकर बनी रही है। जिसके चलते परिवारों व डॉक्टरों को जटिल प्रकिया व कानूनी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। निस्संदेह, हालिया फैसले से भी न्यायिक दिशा-निर्देशों मात्र पर निर्भर रहने की सीमाएं उजागर हुई हैं। बल्कि यहां तक कि देश की शीर्ष अदालत ने भी निष्क्रिय इच्छामृत्यु, लिविंग विल और जीवन को लेकर अंतिम निर्णय को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। निस्संदेह, ऐसे कानून में नैतिक संवेदनशीलता और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के बीच बेहद संतुलन होना चाहिए। यह प्रक्रिया कमजोर रोगियों को दुर्व्यवहार से बचाते हुए, यह भी सुनिश्चित करे कि परिवार और चिकित्सा पेशेवर कानूनी परिणामों के भय के बिना कार्य कर सकें। इस मामले में स्पष्ट प्रोटोकॉल, पारदर्शी चिकित्सा मूल्यांकन और रोगी की स्वायत्तता का सम्मान आवश्यक है। अंतत, निष्कर्ष यह भी है कि जब उपचार असंभव हो तो चिकित्सा उपायों से रोगी की पीड़ा को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। निस्संदेह, शीर्ष अदालत की कारगर सलाह के मद्देनजर देश के नीति-नियंताओं को एक मानवीय कानूनी ढांचा तैयार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चहिए। जो टाली न जा सकने वाली विषम स्थिति में व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने व मरने की अनुमति दे सके। निस्संदेह, देश में इस बाबत एक संवेदनशील कानून बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही ऐसा कानून बनाते वक्त मानवीय संवेदनशीलता तथा कानूनी सुरक्षा कवच के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी होगा। वहीं हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा संकीर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिये किसी व्यक्ति की दबाव में इच्छामृत्यु के लिये परिस्थितियां पैदा न की जा सकें। दुनिया के तमाम विकसित देशों में इस आशंका के चलते ही इच्छामुत्यु को कानूनी रूप देने से परहेज किया गया है। यह जटिल मामला भी है, जिसके निर्धारण के लिये कानूनी स्पष्टता और मामले की गहन निगरानी भी उतनी ही जरूरी है।

खामेनेई की मौत पर मोदी की चुप्पी के कूटनीतिक मायने

> प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की निंदा करने के बजाए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा था कि ऐसे विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने दोहराया कि भारत की नीति हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की रही है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी ने कई तरह के राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरीका द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद भारत में ईरान के दूतावास ने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया था कि वे अमेरिका-इजराइल द्वारा तेहरान पर किए गए हमले और उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिए जाने की कड़ी निंदा करें। ईरानी दूतावास ने कहा था कि भारत स्थित इस्लामिक गणराज्य, ईरान का दूतावास दुनिया भर की आजाद और स्वतंत्रता की पक्षधर सरकारों से इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करने तथा अराजकता एवं आक्रामकता के सामने खामोश नहीं रहने का आह्वान करता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से निंदा का कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की निंदा करने के बजाए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा था कि ऐसे विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने दोहराया कि भारत की नीति हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की रही है। सरकार का कहना है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में बातचीत का रास्ता अपनाना जरूरी है। मोदी की तरफ से अपेक्षित बयान नहीं आने विपक्षी दल भड़क गए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की लक्षित हत्या पर मोदी सरकार की 'चुप्पी' को लेकर कहा कि उनका यह रुख भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने याद दिलाया कि कैसे पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो मई 2024 में अजरबैजान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सात लोगों के साथ मारे गए थे। संजय सिंह ने कहा मोदी जी, आज क्या हुआ? आपने ईरान के प्रेसिडेंट की मौत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। आप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर एक भी शोक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है।

भारत का किसी एक देश के लिए यह दृष्टिकोण कोई अपवाद नहीं है, बल्कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सिद्धांतों के अनुरूप है—जटिल संघर्षों में प्रत्यक्ष गठबंधन से बचना और स्थिरता को प्राथमिकता देना है। भारत की प्रतिक्रिया कई वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया के समान है, जिनमें से कई ने संवेदना व्यक्त करने या सीधे तौर पर निंदा करने से परहेज किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के 57 सदस्यों में से बहुत कम देशों ने शोक व्यक्त किया। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे कुछ देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे निंदनीय बताया, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने घटना को स्वीकार्य नहीं कहा। इराक में तीन दिन का शोक घोषित किया गया। हालांकि अधिकांश मुस्लिम बहुल देशों ने औपचारिक रूप से संवेदना व्यक्त नहीं की।

भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर संयम और संवाद की अपील की। साथ ही ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के सहयोगियों पर किए गए हमलों की आलोचना भी की गई। सरकार का कहना है कि भारत का रुख राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर तय किया गया है। गौरतलब है कि खाड़ी देशों से भारत के द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सरकार ने इसे साम्प्रदायिक रूप देने की बात से दूरी बनाए रखी है। ऐसा नहीं है कि भारत किसी देश के मामले में ऐसा स्टैंड पहली बार लिया हो, यह रुख पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर देखा गया है, जहां भारत ने सीधे बयान देने के बजाय संतुलित कूटनीतिक भाषा का उपयोग किया है।

भारत की अमरीका—ईरान युद्ध पर सतर्क भाषा रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे पूर्व के संकटों से बिल्कुल अलग है, जिनमें भारत ने प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच संबंधों को संतुलित करने का प्रयास किया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की फोन कॉल पर यूएई के बयान में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें संकेत दिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी यूएई द्वारा जवाबी कार्रवाई में उठाए जाने वाले किसी भी कदम का समर्थन करते हैं। बयान में कहा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपनी संप्रभुता की रक्षा, अपनी सुरक्षा की सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे सभी उपायों में भारत की एकजुटता व्यक्त की। नेतन्याहू से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने घटनाक्रम पर भारत की चिंताओं को व्यक्त किया और शीघ्र युद्धविराम का आह्वान किया। गौरतलब है कि मोदी के नेतृत्व में भारत-इजराइल संबंधों को काफी मजबूती मिली है और तेल अवीव नई दिल्ली के शीर्ष रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारों में शुमार है। इजराइल को निर्यात होने वाले हथियारों में भारत की हिस्सेदारी 38% से अधिक है।

हाल के वर्षों में संबंधों में तनाव के बावजूद, ईरान चाबहार बंदरगाह जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं और मध्य एशिया तक क्षेत्रीय पहुंच के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर, भारत ने इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत किया है। ये दोनों ही वर्तमान संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ईरान से व्यापारिक रिश्ते होने के बावजूद कई मौकों पर ईरान ने भारत के खिलाफ प्रतिक्रियाएं दी थी। इस दृष्टि ईरान भारत का विश्वसनीय सांझेदार कभी नहीं रहा। जबकि अमरीका और इजरायल ने भारत के संवेदनीशल मुद्दों पर कभी ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत इजरायल ने हमेशा भारत के रुख का ही समर्थन किया है। साल 2017 से 2024 के बीच अयातुल्ला खामेनेई ने चार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की थी। 2017 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उन्होंने नीति पर सवाल उठाया। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जिसे भारत ने आपत्तिजनक बताया।

ईरान की संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी आलोचना की थी। सितंबर 2024 में खामेनेई ने एक और पोस्ट में भारत का उल्लेख किया, जिसे विदेश मंत्रालय ने भ्रामक बताया। हर बार भारतीय पक्ष ने औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। भारत का तटस्थ रुख उसे एक मध्य मार्ग पर रखता है—अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए किसी भी गुट को नाराज करने से बचता है। अमरीका—ईरान युद्ध के आगे बढ़ने के साथ भारत का रुख भी बदलता रहेगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति किस तरह से सामने आती है—चाहे इससे व्यापक युद्ध छिड़े, राजनयिक वार्ता हो या ईरान में सत्ता परिवर्तन हो।

प्रेरणा

किशोर प्रतिभा से साहित्यिक नक्षत्र बनने की प्रेरक यात्रा

मानव जीवन में प्रेरणा का महत्व अत्यंत गहरा होता है। कई बार एक छोटी-सी सराहना, एक सच्चा मार्गदर्शन या किसी महान व्यक्ति का आशीर्वाद किसी साधारण से दिखने वाले युवक को असाधारण ऊँचाइयों तक पहुँचा देता है। इतिहास और साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ किसी प्रतिभा को सही समय पर मिला प्रोत्साहन उसे सफलता के शिखर तक ले गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी एक ऐसा ही प्रेरणादायक प्रसंग मिलता है, जिसमें एक महान साहित्यकार की प्रेरणा ने एक किशोर प्रतिभा को आगे बढ़ने का साहस दिया और वह आगे चलकर हिंदी साहित्य के आकाश में एक चमकते हुए नक्षत्र के रूप में स्थापित हुआ।

यह घटना उस समय की है जब हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यिक आंदोलन के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र नवोदित लेखकों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर उनसे मिला करते थे। वे मानते थे कि साहित्य केवल विद्वानों की धरोहर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की ऊर्जा और कल्पना से ही उसका वास्तविक विकास संभव है। इसलिए वे युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को पहचानने में विशेष रुचि रखते थे।

एक दिन कुछ किशोरवय नवोदित रचनाकार उनसे मिलने आए। सभी अपने-अपने लेखन और साहित्यिक रुचियों के बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे। उसी समूह में एक किशोर भी था, जिसकी प्रतिभा और ज्ञान ने भारतेंदु जी का विशेष ध्यान आकर्षित किया। वह किशोर उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसकी विद्वता और भाषा ज्ञान देखकर कोई भी चकित हो सकता था। उसे हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, बंगाली और उर्दू भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इतनी कम आयु में इतनी भाषाओं पर अधिकार होना किसी असाधारण प्रतिभा का संकेत था।

जब बातचीत के दौरान उस किशोर ने अपनी नवीनतम मौलिक कृति 'प्रेम पुष्पावली' भारतेंदु जी को दिखाई, तो वे सचमुच आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस कृति को ध्यान से पढ़ा और पाया कि उसमें भाषा की मधुरता, भावों की गहराई और विचारों की परिपक्वता है। इतनी कम उम्र में इतनी सुंदर और सुसंस्कृत भाषा में लेखन करना वास्तव में अद्भुत था। भारतेंदु जी का हृदय उस किशोर की प्रतिभा देखकर गद्गद हो उठा।

उन्होंने उस किशोर को केवल औपचारिक प्रशंसा ही नहीं दी, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए सच्ची प्रेरणा और उत्साह भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यदि वह इसी प्रकार अध्ययन और लेखन में मन लगाकर कार्य करता रहा, तो निश्चित ही भविष्य में हिंदी साहित्य में उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। महान साहित्यकार के मुख से निकले ये शब्द उस किशोर के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे।

कभी-कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो किसी व्यक्ति की दिशा ही बदल देता है। उस दिन मिला यह उत्साहवर्धन उस किशोर के जीवन का वही निर्णायक क्षण बन गया। उसने और अधिक परिश्रम और लगन के साथ अध्ययन और लेखन में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसकी जिज्ञासा, प्रतिभा और मेहनत ने उसे लगातार आगे बढ़ाया।

कहते हैं कि प्रतिभा तभी फलती-फूलती है जब उसे सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता है। उस किशोर के साथ भी यही हुआ। भारतेंदु जी की प्रेरणा ने उसके भीतर आत्मविश्वास का दीप जला दिया। उसने साहित्य को केवल रुचि या शौक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया।

इसके बाद उसने लगातार साहित्य सृजन किया। आश्चर्य की बात यह है कि मात्र तीन वर्षों के भीतर ही उसने कई ललित निबंध लिख डाले। उसके लेखन में भाषा की सहजता, विचारों की स्पष्टता और सामाजिक चेतना का सुंदर समन्वय दिखाई देने लगा। उसकी लेखनी केवल साहित्यिक सौंदर्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें समाज और संस्कृति के प्रति गहरी संवेदना भी झलकती थी।

इतना ही नहीं, उसने अपने विचारों और रचनाओं को व्यापक समाज तक पहुँचाने के लिए अखबार का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। उस समय अखबार निकालना कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए साहस, संगठन क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव आवश्यक होता था। लेकिन उस किशोर ने यह चुनौती भी स्वीकार की और अपने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया।

धीरे-धीरे उसकी पहचान एक प्रतिभाशाली लेखक, विचारक और पत्रकार के रूप में बनने लगी। उसकी रचनाओं में भाषा की सुंदरता के साथ-साथ व्यंग्य, हास्य और सामाजिक आलोचना का भी अद्भुत मिश्रण मिलता था। यही कारण था कि पाठक उसकी रचनाओं को बड़े उत्साह से पढ़ते थे।

समय के साथ वह किशोर हिंदी साहित्य के आकाश में एक उज्ज्वल नक्षत्र बनकर चमकने लगा। उसकी प्रतिभा और साहित्यिक योगदान ने उसे हिंदी जगत में विशेष स्थान दिलाया। वह केवल एक लेखक ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उस प्रतिभाशाली किशोर का नाम था प्रताप नारायण मिश्र। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक उत्कृष्ट रचनाएँ दीं और अपनी लेखनी से साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रतिभा, परिश्रम और साहित्यिक दृष्टि ने उन्हें हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया।

यह प्रेरक प्रसंग हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस दिन उस किशोर की प्रतिभा को अनदेखा कर देते, तो शायद उसे वह आत्मविश्वास और प्रेरणा नहीं मिलती जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी।

साथ ही यह घटना युवाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि प्रतिभा के साथ-साथ परिश्रम, निरंतर अध्ययन और आत्मविश्वास भी आवश्यक होते हैं। यदि किसी के भीतर सीखने की जिज्ञासा और कुछ नया करने की लगन हो, तो वह सीमित परिस्थितियों में भी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है। जीवन में सफलता का मार्ग केवल बड़े अवसरों से नहीं बनता, बल्कि छोटी-छोटी प्रेरणाओं से भी बनता है।

जेन-ज़ी की कुर्बानी और बालेन की बल्ले-बल्ले

नेपाल के हालिया आम चुनाव में कई इतिहास रचे गए। लोकतांत्रिक नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसका चेहरा बने हैं काठमांडू के मेयर बालेन शाह। अन्य बातें समान रही तो उनका प्रधानमंत्री बनना निश्चित माना जा रहा है। मेयर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे बालेन नेपाल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। भ्रष्ट और जोड़तोड़ की राजनीति से आजिज नेपाली युवाओं ने हिंसक प्रतिरोध करके बड़ी कुर्बानियां दी थीं। यही वजह है कि जब चुनाव हुए तो पहली बार सबसे ज्यादा युवा सांसद बने हैं, जिसके चलते एक पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड को छोड़कर जनता ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह बात तो तय है कि युवा आकांक्षाओं के लिए हुए उग्र आंदोलन ने नेपाल की राजनीति की दशा-दिशा बदल दी है।

बहरहाल, नेपाल में बदलाव की आंधी के बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कई मिथ तोड़े हैं। पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल करके भरोसा दिलाया है कि सरकार स्थायी रह सकेगी। जनता ने पार्टी पर पूरा भरोसा जताते हुए नेपाल की प्रतिनिधि सभा में सीधे व समानुपाती पद्धति से सांसदों का बहुमत प्रदान किया है। हालांकि, बालेन शाह के सामने जनाकांक्षाओं का पहाड़ खड़ा है। खासकर युवाओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। निस्संदेह, तीन साल पहले बनी बालेन की पार्टी की कामयाबी तिलस्मी है। लेकिन यह कह पाना कठिन है कि काठमांडू के मेयर का पद संभालने के बाद वे प्रधानमंत्री पद उसी तरह सहजता से चला पाएंगे।

निर्विवाद रूप से नेपाल की मुख्यधारा की राजनीति में बालेन बिल्कुल नये हैं। लेकिन उनकी युवा तुर्क वाली छवि नई पीढ़ी को लुभाती है। यही वजह है कि उनके मधेसी होना भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। यदि वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले मधेसी होंगे। भारत के नजरिये से सवाल यह महत्वपूर्ण है कि उनकी नीति भारत के प्रति कैसी रहती है। सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे परंपरा के अनुसार भारत आते हैं या चीन जाते हैं। माना जाता है कि बालेन शाह किसी विचारधारा के साथ राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली व व्यवहार युवाओं को रिझाता है। फिलहाल कहना कठिन है कि वे भारत के और करीब आते हैं या चीन को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, वे अतीत में चीन के करीब माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के भारत के क्षेत्रों को नेपाल में दर्शाने वाले नक्शे का समर्थन करते नजर आए थे।

वैसे सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में बालेन शाह को लेकर व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह यह भी कि वे किसी आंदोलन की उपज नहीं हैं। उन्हें राजनीतिक बहसों में भी कम ही देखा गया है। हां, एक रैपर के रूप में उनके प्रशंसकों की लंबी फेहरिस्त रही है। तभी वे युवाओं में खासे लोकप्रिय रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसपी में प्रगतिशील व बौद्धिक वर्ग का अनुभव राजकाज चलाने में उनके लिए मददगार हो सकता है। जैसे वे नेपाल की राजनीति के दिग्गज व पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को उनके गढ़ में हराने में कामयाब हो गए। बहरहाल, नेपाल में बनने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सरकार के सामने युवा आकांक्षाओं का बड़ा पहाड़ होगा, जिनको पूरा कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। खासकर लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे देश में पलायन का बड़ा संकट नयी सरकार के सामने होगा। यह अहसास बालेन शाह को भी होगा कि एक मेयर की तुलना में प्रधानमंत्री का पद संभालना कांटों का ताज पहनने जैसा होगा।

भारत सरकार की पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि नई सरकार से कैसे बेहतर संबंध बनाए जाएं। माना जा रहा है कि पार्टी का भारत के प्रति नजरिया सकारात्मक नजर आ रहा है। बेहतर होगा भारत की नीति युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप रहे। पिछले वर्षों में अग्निवीर योजना को लेकर नेपाल में नकारात्मक प्रतिसाद देखने में आया था। वैसे तो दुनिया के एकमात्र हिंदू बहुल देश से सदियों से रोटी-बेटी का रिश्ता रहा है। खासकर राजशाही के दौरान ये संबंध बेहद मधुर रहे हैं। कालांतर वामपंथी रुझान वाले दलों के चलते 'चीन नजदीक दिल्ली दूर' के नारे लगते रहे हैं। वैसे, नई पार्टी की सरकार बनने पर पार्टी की रीति-नीतियों को समझने में कुछ वक्त जरूर लग सकता है।

वैसे भौगोलिक रूप से एक लैंडलॉक्ड देश होने के कारण नेपाल की जरूरतों को पूरा करने में भारत की भूमिका को कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। नेपाल के लोगों की दैनिक जरूरतें भारत के जरिये ही पूरी होती हैं। इस निर्भरता की कोई भी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती है। खासकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेपाल में चीन के प्रभाव को कम करने में भारत इस नये अवसर का बेहतर उपयोग कर सकता है। विश्वास किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में यदि किसी तरह की महत्वाकांक्षाओं का टकराव न हुआ तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार में एक संभावित प्रधानमंत्री के रूप में बालेन पूरी पारी खेल सकते हैं। बशर्ते, आर्थिक संकट व विकास की चुनौती झेल रहे देश में वे युवाओं की आकांक्षाओं में उतरें।

अभियान

देवभूमि की परंपरा का दिव्य उत्सव: रौलान पर्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गाथा

हिमालय की गोद में बसी भारत की पवित्र भूमि सदियों से रहस्य, आस्था और परंपराओं की धरोहर रही है। यहाँ की वादियों में केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं, बल्कि लोकजीवन की गहरी आध्यात्मिकता भी बसती है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में रहने वाले लोग प्रकृति को ही ईश्वर का रूप मानते हैं और अपने जीवन के प्रत्येक उत्सव में प्रकृति और देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन्हीं प्राचीन परंपराओं में से एक है रौलान पर्व, जो हजारों वर्षों से हिमालय की वादियों में मनाया जाता रहा है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति, देवताओं और लोकजीवन के अद्भुत संगम की जीवंत परंपरा है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जनजातीय घाटी किन्नौर घाटी अपने आध्यात्मिक वातावरण और प्राचीन संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहाँ की पहाड़ियाँ, नदियाँ और जंगल स्थानीय लोगों के लिए केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि देवताओं के निवास स्थान माने जाते हैं। इसी क्षेत्र में रौलान पर्व सदियों से मनाया जाता रहा है। लोकमान्यताओं के अनुसार यह उत्सव लगभग पाँच हजार वर्ष पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों द्वारा उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता रहा है। इस पर्व में लोगों की आस्था केवल परंपरा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उनके जीवन की आध्यात्मिक अनुभूति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रौलान पर्व आमतौर पर होली के अगले दिन से प्रारंभ होता है और लगभग पाँच दिनों तक चलता है। जब सर्दियों की कठोरता धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है और वसंत ऋतु की कोमल हवा पहाड़ों में नई ऊर्जा लेकर आती है, तब इस पर्व का आरंभ होता है। स्थानीय लोगों के लिए यह समय प्रकृति के पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जब जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है, तब लोग ईश्वर और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए इस उत्सव को मनाते हैं। इस पर्व की सबसे सुंदर विशेषता इसका आध्यात्मिक वातावरण है। जब रौलान उत्सव आरंभ होता है, तब पूरा क्षेत्र भक्ति और उल्लास से भर उठता है। लोग अपने घरों से निकलकर सामूहिक रूप से एकत्र होते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन, लोकगीतों की मधुरता और सामूहिक नृत्य के बीच वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा अनुभव होती है। ऐसा लगता है मानो पूरी घाटी ही किसी दिव्य उत्सव में शामिल हो गई हो।

रौलान पर्व के दौरान स्थानीय महिलाएँ विशेष रूप से सजती हैं। वे दुल्हन की तरह पारंपरिक आभूषण पहनती हैं और रंग-बिरंगे परिधानों में उत्सव में भाग लेती हैं। उनके चेहरे चांदी और सोने के पारंपरिक गहनों से सजे होते हैं और सिर पर चमकीले रंगों के फूलों की सजावट होती है। हाथ से बुनी हुई पारंपरिक शॉल उनके परिधान को और भी आकर्षक बना देती है। जब वे समूह में नृत्य करती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों की वादियों में सौंदर्य और भक्ति की लहर फैल गई हो। पुरुष भी इस उत्सव में विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। वे दूल्हे की तरह सजते हैं और अपने परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को दर्शाने वाले आभूषण पहनते हैं। इन गहनों में केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि परिवार की स्मृतियाँ और इतिहास भी छिपा होता है। इस प्रकार यह उत्सव लोगों को अपने पूर्वजों और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी बन जाता है। रौलान पर्व से जुड़ी एक प्राचीन लोककथा भी लोगों के बीच प्रचलित है। कहा जाता है कि सर्दियों के महीनों में पर्वतीय परियाँ धरती पर आती हैं और हिमालय की वादियों में निवास करती हैं। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, तब उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है ताकि प्रकृति का नया चक्र आरंभ हो सके। यह विदाई केवल एक लोककथा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि इन परियों का आशीर्वाद ही उन्हें समृद्धि, खुशहाली और नई फसल का वरदान देता है। उत्सव की शुरुआत बड़े ही सरल और पवित्र तरीके से होती है। पहले दिन दो या तीन वैवाहिक जोड़े पारंपरिक वेशभूषा में सजकर आते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। वे नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और पूरे समुदाय के साथ उत्सव की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन पाँच जोड़े इस आयोजन में भाग लेते हैं और उत्सव का वातावरण और अधिक आनंदमय हो जाता है। तीसरे दिन तक आसपास के गाँवों से बड़ी संख्या में लोग इस पर्व में शामिल होने के लिए आने लगते हैं। किन्नौर के आसपास स्थित गाँव जैसे सांगला और कल्पा के लोग भी इस उत्सव में बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। जब ये सभी लोग पारंपरिक परिधानों में एकत्र होते हैं और ढोल-नगाड़ों की धुन पर नृत्य करते हैं, तो पूरा क्षेत्र भक्ति और आनंद से भर उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो पर्वत, नदियाँ और आकाश भी इस उत्सव के साक्षी बनकर आनंदित हो रहे हों। लंबे समय तक यह पर्व केवल स्थानीय लोगों तक ही सीमित रहा। पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाहरी दुनिया को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन आधुनिक युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस स्थिति को बदल दिया। कुछ समय पहले कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स और फोटोग्राफरों ने इस उत्सव को देखा और इसकी तस्वीरें तथा वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए। इन तस्वीरों में पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग, हिमालय की पृष्ठभूमि में नृत्य करते हुए समूह और रंगों से भरा उत्सव दिखाई देता था। यह दृश्य इतना सुंदर और आकर्षक था कि देखते ही देखते यह इंटरनेट पर वायरल हो गया। दुनिया भर के लोगों ने इन तस्वीरों को देखा और इस अनोखी परंपरा के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई।

हालाँकि स्थानीय लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उनके लिए यह उत्सव सदियों से उनके जीवन का हिस्सा रहा है। वे इसे किसी प्रसिद्धि या लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि अपनी आस्था और परंपरा के कारण मनाते हैं। उनके लिए यह पर्व देवताओं के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के प्रति सम्मान और समुदाय के बीच प्रेम और एकता का प्रतीक है।

आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और आधुनिक जीवन शैली पारंपरिक मूल्यों को पीछे छोड़ती जा रही है, तब रौलान पर्व जैसी परंपराएँ हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी और समृद्ध हैं। हिमालय की वादियों में मनाया जाने वाला यह उत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है।

रौलान पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन की वास्तविक खुशी सामूहिक उत्सव, प्रकृति के प्रति सम्मान और परंपराओं के संरक्षण में छिपी होती है। जब लोग मिलकर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और देवताओं का स्मरण करते हैं, तब उनके बीच का प्रेम और विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है।

इस प्रकार हिमाचल की पवित्र वादियों में मनाया जाने वाला रौलान पर्व केवल एक जनजातीय उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम अपनी परंपराओं को सच्चे मन से संजोकर रखें, तो वे समय की सीमाओं को पार करते हुए आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रह सकती हैं। हिमालय की शांत और दिव्य भूमि में गूंजता यह उत्सव आज भी लोगों को यह संदेश देता है कि प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का दिव्यांगजनों के प्रति संवेदना स्पर्शी दृष्टिकोण

मोटराइज्ड ट्राइसिकल तथा जॉयस्टिक व्हीलचेयर से राज्य के दिव्यांगजनों का रोजमर्रा का जीवन अधिक सरल एवं सुगम बनेगा

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 5676 दिव्यांग लाभार्थियों को कुल 36 करोड़ रुपए की मोटराइज्ड ट्राइसिकल तथा जॉयस्टिक व्हीलचेयर का वितरण किया
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा राज्य मंत्री की उपस्थिति
- मुख्यमंत्री का सादी जॉयस्टिक व्हीलचेयर के स्थान पर फोल्डिंग जॉयस्टिक व्हीलचेयर के लिए 1.10 लाख रुपए की सहायता देने का दिव्यांग हितकारी निर्णय
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रकार की दिव्यांगता के सहायता लाभ प्राप्त करने की लाभार्थी की पात्रता आयु सीमा 18 से घटाकर 10 वर्ष की गई

जीएनएस)। गांधीनगर : दिव्यांगजन अपने रोजमर्रा के कामकाज सरलता से कर सकें तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन में सुगमता रहे; ऐसे दिव्यांग हित दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राइसिकल एवं जॉयस्टिक व्हीलचेयर देने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर में पहली बार राज्य के 34 जिलों के 4000 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल तथा 1676 दिव्यांगजनों को जॉयस्टिक व्हीलचेयर सहित कुल 36.7 करोड़ रुपए की साधन सहायता का सांकेतिक रूप से वितरण किया।

मुख्यमंत्री की प्रेरणा से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा गत वर्ष 2025-26 के बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तद्अनुसार; इस साधन सहायता का वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में लगभग 40 दिव्यांगजनों को इन मोटराइज्ड ट्राइसिकल तथा जॉयस्टिक व्हीलचेयर का सांकेतिक रूप से वितरण किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा, राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील तथा मुख्य सचिव श्री एम. के. दास भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दिव्यांग लाभार्थियों के साथ भावपूर्ण संवाद कर उनके जीवन में इस साधन सहायता से आने वाले परिवर्तन तथा सुगमता के बारे में बातचीत की।

यह योजना कार्यरत होने से पहले दिव्यांग साधन सहायता योजनांतर्गत हाथ से चलाई जा सकने वाली सादी ट्राइसिकल तथा व्हीलचेयर दी जाती थी। इसके कारण दिव्यांगजनों को अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता था तथा दूर तक आने-जाने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा दिव्यांगजनों की इस वेदना को समझकर उन्हें उससे मुक्ति दिलाने के लिए किए गए संवेदनशील निर्णय के फलस्वरूप दिव्यांग लाभार्थियों को अब मोटराइज्ड ट्राइसिकल तथा जॉयस्टिक व्हीलचेयर दी जाएंगी। दिव्यांग लाभार्थियों को ये नए साधन मिलने से ट्राइसिकल तथा व्हीलचेयर को हाथ से चलाने से मुक्ति मिलेगी और उनकी रोजमर्रा की दैनिक क्रिया में और उनके कार्यस्थल पर पहुँचने में बहुत ही आसानी होगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दिव्यांगजनों की सुगमता के लिए एक और संवेदनशील निर्णय लेकर इस वर्ष 2026-27 से जॉयस्टिक व्हीलचेयर देने की योजना में भी सहायता का मानदंड बढ़ाने के दिशा-निर्देश दिए हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मल्टीपल डिसेबिलिटी प्रकार की दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को आवागमन में सुगमता रहे और यात्रा के दौरान वे जॉयस्टिक व्हीलचेयर अपने साथ रख सकें; इस उद्देश्य से सादी जॉयस्टिक व्हीलचेयर के स्थान पर अब फोल्डिंग जॉयस्टिक व्हीलचेयर देने के लिए सहायता राशि में वृद्धि कर 1.10 लाख रुपए की गई है।

इतना ही नहीं; मुख्यमंत्री ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रकार की दिव्यांगता वाले लाभार्थी के लिए सहायता लाभ प्राप्ति की पात्रता आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने का भी निर्णय किया है।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को लाभार्थी सहायता के लिए सेचुरेशन एप्रोच अपनाकर एक भी जरूरतमंद दिव्यांग लाभार्थी राज्य सरकार की साधन सहायता से वंचित न रहे; इसके लिए भी निर्देश दिए हैं।

दिव्यांगजनों के लिए ये सहायक साधन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा बनाए गए हैं।

गांधीनगर में इस साधन सहायता वितरण अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव डॉ. हर्षद पटेल, समाज सुरक्षा निदेशक श्री विक्रम जादव, वरिष्ठ अधिकारी तथा दिव्यांग लाभार्थी व उनके परिजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में राज्य में पीएनजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई

राज्य में पाइपलाइन के जरिए घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है

जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और पेट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा स्थिति को लेकर शुक्रवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइपलाइन गैस वितरण नेटवर्क उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में यदि रेस्टोरेंट, होटल, शैक्षणिक संस्थाएं और सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं अपनी जरूरत के अनुसार नए पीएनजी कनेक्शन की मांग करते हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से कनेक्शन दे दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में प्राकृतिक गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की समीक्षा में बताया गया कि राज्य में नागरिकों को पाइपलाइन के जरिए घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति जारी है और फिलहाल उनके लिए राज्य में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोना खंधार, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के प्रधान सचिव श्री अश्विनी कुमार, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक (एमडी) श्रीमती अवंतिका सिंह और मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अहमदाबाद मंडल में कांकरिया स्थित आधुनिक मेकेनाइज्ड लॉन्ड्री: यात्रियों को मिल रहा है स्वच्छ और हाईजिन बेडरोल

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता की लिनेन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांकरिया स्थित BOOT मॉडल आधारित आधुनिक मेकेनाइज्ड लॉन्ड्री का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

यह अत्याधुनिक लॉन्ड्री लंबी दूरी की ट्रेनों में एसी श्रेणी के यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले बेडरोल की धुलाई, सफाई और प्रबंधन को वैज्ञानिक एवं स्वचालित तकनीक के माध्यम से सुनिश्चित करती है।

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वर्ष 2022-23 में 67 यंत्रीकृत लॉन्ड्री में से निरीक्षण के लिए चुनी गई 19 लॉन्ड्री में कांकरिया लॉन्ड्री को सबसे किफायती, कुशल और पर्यावरण अनुकूल पाया गया।
- लगभग 1800 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थापित इस इकाई में से 1300 वर्गमीटर क्षेत्र संचालन के लिए उपयोग में लिया जा रहा है।
- इस परियोजना की धुलाई क्षमता प्रति शिफ्ट 8 टन (कुल 16 टन) है, जबकि प्रतिदिन लगभग 19.5 टन लिनेन (18 टन बेडरोल एवं 1.5 टन अन्य वस्त्र) की धुलाई की जा सकती है।
- प्रतिदिन लगभग 43,000 बेडशीट,21000 तकिया कवर सहित

कुल 72000 लिनन की धुलाई की जाती है, जिससे करीब 12 ट्रेनों के लिए बेडरोल उपलब्ध कराया जाता है।

- वर्तमान में लिनेन धुलाई का अनुबंध दर 16.65 प्रति किलोग्राम अथवा प्रति बेडरोल निर्धारित है तथा इस इकाई में लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं।
- पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए थर्मिक फ्लूइड बॉयलर में ईंधन के रूप में मूंगफली के छिलकों (Groundnut Shell) का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और ऊर्जा दक्षता बढ़ती है।
- लॉन्ड्री में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के माध्यम से भूजल को आरओ प्रणाली से शुद्ध कर धुलाई में उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1,20,000 लीटर पानी की खपत होती है।

शिकायतों में उल्लेखनीय कमी

- इन उपायों के परिणामस्वरूप:
- लिनेन संबंधी शिकायतों में लगभग 40% की कमी आई है।
- गंदे लिनेन से संबंधित शिकायतों में लगभग 34% की कमी दर्ज की गई है।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार:

- 2023: 6075 लिनेन शिकायतें
- 2024: 5962 शिकायतें (113 शिकायतें कम, 1.86% सुधार)
- 2025: 3669 शिकायतें (2293 शिकायतें कम, 38.46% सुधार)

इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 एवं 2025 में यात्रा के दौरान लिनेन चोरी/गायब होने की घटनाओं से लगभग 4.21 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया।

यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम

- Comprehensive Linen Management System लागू कर लिनेन की धुलाई एवं वितरण की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया है।
- पुराने और घिसे हुए लिनेन को नियमित रूप से बदलकर लिनेन की गुणवत्ता तथा स्वच्छता के मानकों को बेहतर किया जा रहा है।
- वर्ष 2024 में लगभग 23% लिनेन 2 वर्ष से अधिक पुराने थे। इसे लक्ष्यबद्ध तरीके से कम करते हुए अब 0% कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में अहमदाबाद मंडल में 2 वर्ष से अधिक पुराना कोई भी लिनेन उपयोग के लिए नहीं दिया जा रहा है।
- AC कोच अटेंडेंट्स के लिए नियमित काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि यात्रियों के साथ शिष्ट और जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए उन्हें Masked Reservation Chart उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की निजता बनाए रखते हुए उनकी सुविधा के स्तर में सुधार हो सके।
- सभी AC कोच अटेंडेंट्स के लिए शतप्रतिशत रूप से प्रस्थान एवं आगमन के समय ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट किए जाते हैं, जिससे अनुशासन तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके
- अहमदाबाद मंडल ने प्रयोगात्मक तौर पर गुजरात मेल एक्सप्रेस में ब्लैंकेट कवर देने की शुरुआत की है जिसे यात्रियों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर संवाद जारी, वार्ता रुकने की खबरों को सरकार ने बताया गलत

जीएनएस)। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत पर हाल के दिनों में कई तरह की खबरें सामने आई थीं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दोनों देशों के बीच यह वार्ता रुक गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। सरकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में चर्चा आगे बढ़ रही है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मीडिया के एक हिस्से में प्रकाशित उस रिपोर्ट पर ध्यान गया है जिसमें कहा गया था कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत ठप हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है और दोनों देशों के बीच वार्ता नियमित रूप से चल रही है।

सरकार के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। दोनों पक्ष ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए समान रूप से लाभकारी हो। इस संभावित समझौते से व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही काफी मजबूत माने जाते हैं। दोनों देश एक-दूसरे के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्रस्तावित व्यापार समझौते को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसी बीच वैश्विक व्यापार जगत में कुछ नई गतिविधियों के कारण इस विषय पर चर्चा और तेज हो गई है। हाल ही में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की औद्योगिक नीतियों और व्यापारिक प्रथाओं की जांच शुरू की है। यह जांच Trade Act of 1974 Section 301 के तहत की जा रही है। इस प्रक्रिया में भारत और चीन सहित लगभग 16 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से वैश्विक व्यापार नीतियों और नियमों पर नई बहस शुरू हो गई है।

इस संदर्भ में अमेरिका की व्यापार नीति में भी कुछ अहम फैसले सामने आए हैं। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका में व्यापारिक शुल्क को लेकर नई घोषणाएँ की गई हैं। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगाए गए कुछ जवाबी शुल्कों को समाप्त किए जाने के बाद 24 फरवरी से 150 दिनों की अवधि के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। बाद में इस शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।

इन घटनाओं के बीच भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दोनों देशों के बीच संतुलित और व्यापक व्यापार समझौता होता है, तो इससे न केवल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा निर्यात बाजार है, जबकि अमेरिका के लिए भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच तकनीक, विनिर्माण, कृषि और सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ हैं। ऐसे में व्यापार समझौते की दिशा में चल रही बातचीत को दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि वार्ता रुकने की खबरें केवल अटकलों पर आधारित थीं। वास्तविकता यह है कि दोनों देश लगातार संवाद के माध्यम से एक ऐसे समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो उनके व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बना सके। आने वाले समय में इस बातचीत के नतीजों पर दुनिया भर के व्यापारिक समुदाय की नजर बनी रहेगी, क्योंकि यह समझौता वैश्विक व्यापार संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के उपलक्ष्य में आरपीएफ महिला कर्मचारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

जीएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के उपलक्ष्य में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 13 मार्च 2026 को मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की महिला कर्मचारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना तथा विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर की समय पर जांच एवं उसकी रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूक करना था।

इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुश्री द्वारा आरपीएफ की महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर के दौरान पैप स्मीयर (Pap Smear) टेस्ट सहित सर्वाइकल कैंसर से संबंधित अन्य आवश्यक जांचें भी की गईं। डॉ. अनुश्री ने उपस्थित महिला कर्मचारियों को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, कारण, रोकथाम तथा नियमित जांच के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और उचित उपचार से इस गंभीर रोग को प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रित किया जा सकता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. मनोज कुमार की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था, समन्वय एवं संचालन सहायक नर्सिंग अधिकारी (एएनओ), भावनगर द्वारा किया गया, जिनके प्रयासों से यह शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

शिविर में आरपीएफ की महिला कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए समय-समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया।

वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी का पर्दाफाश, कैंट स्टेशन पर 3.54 करोड़ का सोना बरामद

जीएनएस)। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये का सोना बरामद किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दो किलो से अधिक सोने के बिस्किट जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3.54 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई नियमित जांच के दौरान की गई। रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस टीम यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस से उतरने वाले दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की और उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से सोने के कई बिस्किट बरामद हुए, जिनका कुल वजन दो किलो से अधिक पाया गया।

इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जीआरपी कैंट थाना प्रभारी राजोल नागर ने बताया कि बरामद सोने को तुरंत पुलिस ने कब्जे में ले लिया और दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती जांच में यह मामला साधारण नहीं बल्कि संगठित तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सतारा निवासी बालासो और पुणे निवासी तेजस के रूप में हुई है।

सप्ताह के दौरान क्रूड ऑयल वायदा में 1488 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा 598 रुपये और चांदी वायदा 5771 रुपये तेज

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 6 से 12 मार्च के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2211304.08 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 317638.62 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 1893658.49 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 40098 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 85829.63 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 149497.12 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 161040 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 163577 रुपये और नीचे में 159320 रुपये पर पहुंचकर, 159673 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 598 रुपये या 0.37 फीसदी बढ़कर 160271 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 119 रुपये या 0.09 फीसदी गिरकर 131276 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 9 रुपये या 0.05 फीसदी लुढ़ककर 16490 रुपये प्रति 1 ग्राम सप्ताह के अंत में बंद हुआ। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 160863 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 163590 रुपये और नीचे में 159400 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 554 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 160367 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 161499 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 164000 रुपये और नीचे में 160506 रुपये पर पहुंचकर, 161141 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 218 रुपये या 0.14 फीसदी की तेजी के संग 161359 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 267950 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में

279463 रुपये के उच्च और 260743 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 262191 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5771 रुपये या 2.2 फीसदी की बढ़त के साथ 267962 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 4795 रुपये या 1.78 फीसदी बढ़कर सप्ताह के अंत में 273614 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 4719 रुपये या 1.75 फीसदी की तेजी के संग 273720 रुपये प्रति किलो सप्ताह के अंत में हुआ।

मेटल वर्ग में 18459.06 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 7.45 रुपये या 0.62 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1202.3 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 4.05 रुपये या 1.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 325.35 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 19.35 रुपये या 5.85 फीसदी बढ़कर 349.95 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 25 पैसे या 0.13 फीसदी की नरमी के साथ 188.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

- कमोडिटी वायदाओं में 317638 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 1893658 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 149497 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40098 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 149644.14 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 7316 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 10549 रुपये के उच्च और 7207 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 1488 रुपये या 20.34 फीसदी की मजबूती के साथ 8804 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 1492 रुपये या 20.4 फीसदी की तेजी के संग 8806 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 274.5 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 322.9 रुपये के उच्च और 271.9 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 273.6 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 24 रुपये या 8.77 फीसदी की मजबूती के साथ 297.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 24.1 रुपये या 8.81 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 297.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 947.1 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 45.6 रुपये या 4.81 फीसदी की तेजी के संग 994.1 रुपये प्रति किलो हुआ। इलायची का मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 2477 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में यह वायदा 49 रुपये या 1.98 फीसदी की बढ़त के साथ 2525 रुपये हुआ।

कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के दौरान एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 92035.73 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 57461.39 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 10761.96 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 5011.74 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 57.98 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2572.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 117287.92 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 32235.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 33.41 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7824 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 41540 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 14867 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 209674 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 30147 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5941 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 13988 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 49644 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17371 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 19567 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 39380 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 40590 के उच्च और 39356 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 385 पॉइंट बढ़कर 40098 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

दुबई और ग्वांगझू जैसा वैश्विक ट्रेडिंग हब बनने की ओर दक्षिण गुजरात की दौड़

दक्षिण गुजरात को वैश्विक सप्लाई चेन में स्थान दिलाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सड़क मार्ग सुधार के लिए 1,185 करोड़ रुपए मंजूर किए

जीएनएस)। गांधीनग : गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दक्षिण गुजरात में स्थित सड़क मार्गों को चौड़ा करने तथा उनमें सुधार के लिए 1,185 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सूरत इकोनॉमिक रीजन (एसईआर) को दुबई तथा चीन के ग्वांगझू जैसे वैश्विक ट्रेडिंग हब की तर्ज पर विकसित करना है और सूरत को वैश्विक सप्लाई चेन में जोड़ना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मंजूर किए गए इन प्रोजेक्टों में सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी तथा डांग जिलों में कुल 383 किलोमीटर सड़क मार्ग को समाविष्ट करने वाले 24 कार्य शामिल हैं। यह कदम लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी सुधारने और दक्षिण गुजरात को वैश्विक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित करने वाला है।

भारत सरकार द्वारा सूरत इकोनॉमिक रीजन (एसईआर) को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए एक आर्थिक मास्टर प्लान तैयार किया गया था और ठीक 17 महीने पहले इस मास्टर प्लान को मुख्यमंत्री के करकमलों से सूरत में लॉन्च किया गया था। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य वर्ष 2047 तक सूरत शहर तथा समग्र दक्षिण गुजरात को देश के महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र के रूप में विकसित करना है।

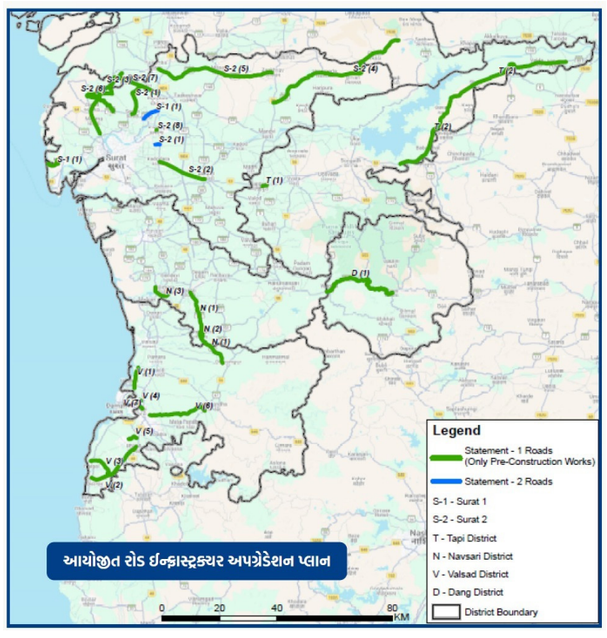

सूरत का मास्टर प्लान केवल ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए इस व्यापक आर्थिक मास्टर प्लान के विषय में मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, "सूरत इकोनॉमिक रीजन का यह आर्थिक मास्टर प्लान केवल एक ब्लूप्रिंट नहीं; बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में दृष्टिवान, गतिशील एवं सर्वसमावेशी विकास की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।"

जिलेवार आवंटन में सूरत को 631 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, कारण कि गुजरात के विकास में सूरत की मुख्य भूमिका रही है। वलसाड जिले को 264 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि शेष राशि नवसारी, तापी तथा डांग जिलों में कार्यों के लिए आवंटित की गई है।

अधिकारियों के अनुसार ये निवेश दक्षिण गुजरात में औद्योगिक क्लस्टरों, बंदरगाहों तथा लॉजिस्टिक्स हब के बीच की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए हैं। विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्र तथा बेहतरीन ढंग से जुड़े हुए आंतरिक प्रदेश अत्याधुनिक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभर रहे होने के कारण राज्य सरकार बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

मजबूत औद्योगिक आधार तथा रणनीतिक स्थान के कारण सूरत को देश में आर्थिक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए चुने गए चार पायलट शहरी क्षेत्रों में स्थान मिला है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सूरत में अनेक ऐसे उद्योग कार्यरत हैं, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सूरत विश्वभर में कपड़ा उत्पादन तथा हीरा पॉलिशिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा; यहाँ केमिकल उद्योग, लघु एवं मध्यम कद के क्लस्टर तथा लॉजिस्टिक्स सेवाएँ भी मजबूत हैं।

भरूच जिले में केमिकल, फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोकेमिकल उद्योगों का मजबूत आधार है, जबकि नवसारी कृषि, फूड प्रोसेसिंग एवं छोटे पैमाने के उत्पादनों के लिए विख्यात है।

तापी जिले में एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योग, कागज उत्पादन तथा डेयरी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। वलसाड जिले में केमिकल उद्योगों, व्यापार तथा पर्यटन संबंधित गतिविधियों का संयोजन देखने को मिलता है, जबकि डांग जिला अधिकांश रूप से वनीय एवं आदिवासी क्षेत्र वाला होने के कारण उसकी आर्थिक गतिविधियाँ कृषि, वन उत्पादन तथा मूलभूत सेवाओं पर आधारित हैं।

सूरत आर्थिक प्रदेश के विकास की ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद अब राज्य सरकार का लक्ष्य उत्पादन केन्द्रों तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच दूरी कम करके सूरत-दक्षिण गुजरात को वैश्विक ट्रेडिंग हब स्थापित करना है, जो वैश्विक सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन सकता है।

हाल में दक्षिण गुजरात की प्रतिव्यक्ति जीडीपी लगभग 4,600 डॉलर है, जिसे 2047 तक बढ़ाकर 45,000 डॉलर से अधिक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सुसंगत (तार्किक) आयोजन तथा बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास जरूरी है। सड़क मार्ग सुधार तथा विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 1,185 करोड़ रुपए की मंजूरी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य सरकार की विकास रणनीति में टिकाऊ विकास, आर्थिक विविधता तथा संतुलित प्रादेशिक (क्षेत्रीय) विकास पर बल दिया गया है, जिसके द्वारा सूरत तथा आसपास के जिलों को मजबूत आर्थिक शक्ति केन्द्र के रूप में विकसित करने का उद्देश्य है।

सूरत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसके विकास को गति देगी

सूरत का रणनीतिक भौगोलिक स्थान, सुदृढ़ परिवहन कनेक्टिविटी तथा विकसित औद्योगिक ढाँचा उसे नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए अनुकूल बनाते हैं। प्रदेश को एक्सप्रेसवे, रेलवे कनेक्टिविटी, समुद्री बंदरगाहों, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का लाभ मिलता है। राज्य सरकार ने भविष्य के विकास के लिए टिकाऊ कृषि, रियल एस्टेट, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान भी की है, जिससे इस प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आर्थिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके।

पश्चिम रेलवे के बोरीवली एवं भायंदर स्टेशनों के बीच ब्लॉक,तथा प्रभादेवी स्टेशन पर मेजर ब्लॉक

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालन कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए बोरीवली एवं भायंदर स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर जम्बो ब्लॉक तथा प्रभादेवी स्टेशन पर शनिवार/रविवार, 14/15 मार्च, 2026 की मध्यरात्रि में प्रभादेवी रोड ओवर ब्रिज (ROB) के गर्डर के डी-लॉन्चिंग कार्य हेतु सभी लाइनों पर मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोरीवली एवं भायंदर स्टेशनों के बीच 00:15 बजे से 03:45 बजे तक लिया ब्लॉक जाएगा, जबकि प्रभादेवी स्टेशन पर 01:30 बजे से 06:00 बजे तक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

बोरीवली–भायंदर ब्लॉक के दौरान फास्ट लाइन की सभी ट्रेनें विरार/वसई रोड और बोरीवली के बीच स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी। प्रभादेवी स्टेशन पर ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी तथा कुछ सेवाओं को दादर और बांद्रा से शॉर्ट टर्मिनेट कर वहीं से रिटर्न किया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान चर्चगेट और प्रभादेवी स्टेशनों के बीच तथा माटुंगा रोड और माहिम स्टेशनों पर कोई उपनगरीय ट्रेन सेवा परिचालित नहीं होगी।

इन ब्लॉकों के कारण कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को सूरत और विरार के बीच रेगुलेट किया जाएगा अथवा रिशेड्युल किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1.13 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09184 वाराणसी–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को 2 घंटा रेगुलेट किया जाएगा।

2.14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को 1 घंटा 45 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

3.14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12928 एकता नगर–दादर एक्सप्रेस को 1 घंटा रेगुलेट किया जाएगा।

4.14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद–दादर एक्सप्रेस को 1 घंटा रेगुलेट किया जाएगा।

5.14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09052 भुसावल–दादर एक्सप्रेस को 45 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

6.15 मार्च, 2026 को मुंबई सेंट्रल 05:40 बजे यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद एक्सप्रेस 06:10 बजे प्रस्थान करेगी, अर्थात यह ट्रेन 30 मिनट रिशेड्युल किया जाएगा।

रविवार, 15 मार्च, 2026 को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

पश्चिम रेलवे ने लगातार चौथे वर्ष 100 मिलियन टन माल लदान का आँकड़ा पार किया

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 12 मार्च, 2026 को प्रारंभिक माल लदान में 100 मिलियन टन का महत्वपूर्ण आँकड़ा पार कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही पश्चिम रेलवे ने लगातार चौथे वर्ष 100 मिलियन टन माल लदान का आँकड़ा पार किया है, जो माल परिवहन के क्षेत्र में उसके सुदृढ़ और निरंतर प्रदर्शन तथा देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को सशक्त बनाने में पश्चिम रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कई वस्तुओं के लदान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कंटेनर लदान 33.66 मिलियन टन रहा, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। उर्वरक लदान 18.92 मिलियन टन रहा, जिसमें लगभग 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। खाद्यान्न लदान 1 मिलियन टन रहा, जिसमें 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लौह एवं इस्पात का लदान 0.69 मिलियन टन रहा, जिसमें लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीमेंट लदान 14.53 मिलियन टन रहा, जिसमें 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य वस्तुओं का लदान भी मजबूत रहा और यह 15.94 मिलियन टन दर्ज किया गया, जिसमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अप्रैल 2025 से 12 मार्च 2026 की अवधि के दौरान वस्तुवार माल लदान में कोयला, उर्वरक, कंटेनर, पीओएल, सीमेंट, खाद्यान्न, लौह एवं इस्पात तथा अन्य वस्तुएँ शामिल हैं, जिससे कुल माल लदान 100.02 मिलियन टन तक पहुँच गया। वर्ष के दौरान पश्चिम रेलवे ने सनोसरा, भीमासर, वरतेज, वडोदरा मार्शलिंग यार्ड, कड़ी, गांधीधाम आदि विभिन्न स्थानों से औद्योगिक नमक, प्याज, ऑटोमोबाइल आदि जैसी वस्तुओं में माल परिवहन के नए स्रोत भी विकसित किए गए। इससे पश्चिम रेलवे के माल परिवहन पोर्टफोलियो को और अधिक मजबूती मिली है।

पश्चिम रेलवे नए माल परिवहन स्रोतों को आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप माल परिवहन सेवाएँ प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जा सकी है।

बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जीएनएस)। राजधानी पटना में उस समय प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई जब बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना सामने आई। इस ईमेल के मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं और विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल कड़ा कर दिया गया। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है और धमकी देने वाले की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विधानसभा से जुड़े आधिकारिक तंत्र को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जैसे ही यह सूचना सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए और विधानसभा परिसर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रेम कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई और पूरे मामले की समीक्षा की। बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि धमकी से जुड़े पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रभारी सचिव ख्याति सिंह को निर्देश दिया कि इस घटना की सूचना तुरंत राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दी जाए। इसके तहत अमृत लाल मीणा और विनय कुमार को भी मामले की जानकारी उपलब्ध कराई गई, ताकि राज्य स्तर पर सुरक्षा और जांच की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की मदद से भवन के विभिन्न हिस्सों की जांच की गई। सुरक्षा कर्मियों ने परिसर के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में हर संदिग्ध गतिविधि पर विशेष नजर रखनी शुरू कर दी। इसके अलावा प्रवेश द्वारों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और आने-जाने वाले सभी लोगों की कड़ी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद साइबर विशेषज्ञों को भी जांच में शामिल किया गया है।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

श्रेष्ठ शिक्षा से विकसित गुजरात का निर्माण

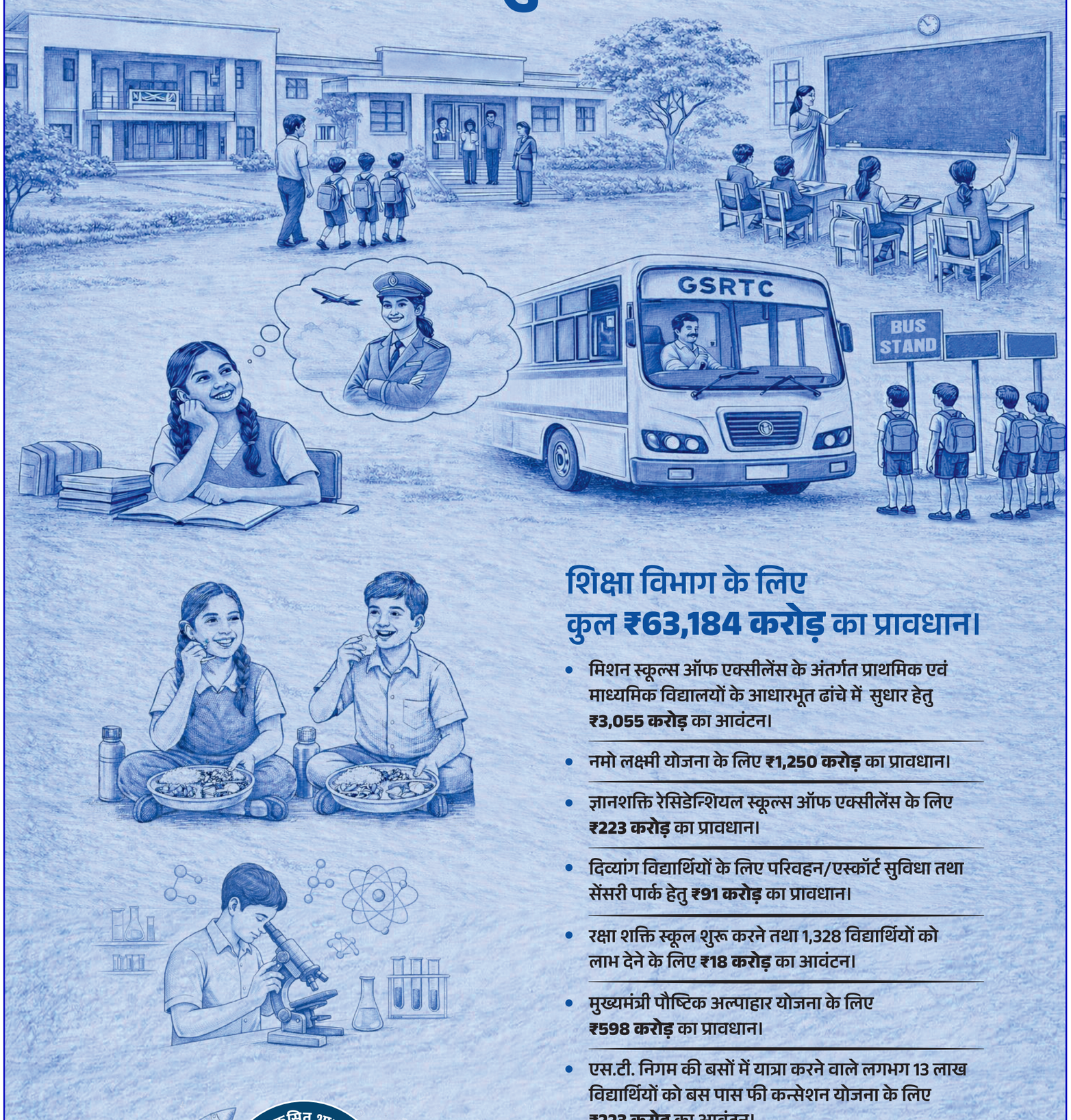

शिक्षा विभाग के लिए कुल ₹63,184 करोड़ का प्रावधान।

- मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु **₹3,055 करोड़** का आवंटन।
- नमो लक्ष्मी योजना के लिए **₹1,250 करोड़** का प्रावधान।
- ज्ञानशक्ति रेसिडेन्शियल स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए **₹223 करोड़** का प्रावधान।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा तथा सेंसरी पार्क हेतु **₹91 करोड़** का प्रावधान।
- रक्षा शक्ति स्कूल शुरू करने तथा 1,328 विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए **₹18 करोड़** का आवंटन।
- मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के लिए **₹598 करोड़** का प्रावधान।
- एस.टी. निगम की बसों में यात्रा करने वाले लगभग 13 लाख विद्यार्थियों को बस पास फी कन्सेशन योजना के लिए **₹223 करोड़** का आवंटन।

"राज्य के हर विद्यार्थी को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्तम पोषण प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। शिक्षा विभाग का यह बजट सही मायनों में 'शिक्षित गुजरात, समृद्ध गुजरात' के हमारे विजन को साकार करेगा।"

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात